परेशानी | दोपहिया और चारपहिया वाहन एक साथ पहुंचने से लग रहा जाम

महाविद्यालय के बाहर छुट्टी के बाद ट्रैफिक का दबाव

नवभारत , जबलपुर । मढ़ाताल स्थित महिला महाविद्यालय विद्यालय के बाहर छुट्टी के समय प्रतिदिन ट्रैफिक का दबाव देखने को मिल रहा है। विद्यालय मुख्य शहर के व्यस्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां सामान्य समय में भी वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। छुट्टी के समय बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक, ऑटो रिक्शा, दोपहिया और चारपहिया वाहन एक साथ पहुंचने से सड़क पर कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन जाती है। नवभारत की टीम को विद्यालय प्रबंधन ने बताया है कि स्कूल दो शिफ्टों में संचालित होता है, जिससे सुबह और दोपहर दोनों समय विद्यार्थियों की आवाजाही अधिक रहती है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं दो सुरक्षा गार्ड भी दो अलग-अलग शिफ्टों में तैनात रहते हैं।

अभिभावकों ने रखी अपनी शिकायत

विद्यालय के बाहर मौजूद कई अभिभावकों ने बताया कि छुट्टी के समय रोजाना ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। उनका कहना है कि बच्चों को लेने आने वाले वाहनों की अधिक संख्या के कारण सड़क पर लंबी कतारें लग जाती हैं और कई बार काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।

यातायात पुलिस से समन्वय, व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास

विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस से लगातार समन्वय बनाए रखा जाता है। ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर विद्यालय के बाहर राउंड लगाकर यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास भी करती है। इसके बावजूद छुट्टी के समय अचानक बढ़ने वाली भीड़ और वाहनों के दबाव के कारण स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं रह पाती।

इनका कहना है

ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम दोनों मिलकर इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे है । हमने पैट्रोलिंग की जाती है ।

संतोष कुमार शुक्ला
डीएसपी , यातायात

सात हजार करोड़ का बजट, फिर भी स्कूलों में शिक्षक नहीं

जबलपुर। मप्र की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर कैग की रिपोर्ट ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब अब सरकार को हाईकोर्ट में देना होगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने 2025 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट के आधार पर दायर इंदौर के अधिवक्ता सौरभ त्रिपाठी की जनहित याचिका को बेहद गम्भीरता से लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। दायर जनहित याचिका में आरोप है कि 7,165 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के बावजूद प्रदेश के 1895 सरकारी स्कूल बिना एक भी शिक्षक के चल रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बिना विद्यार्थियों वाले स्कूलों में शिक्षक पदस्थ हैं। कोर्ट ने मामले को जनहित और बच्चों के शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच 66,814 सरकारी स्कूलों के आडिट में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं।

एमबीबीएस छात्रों की परीक्षा के पेटर्न में बड़ा बदलाव

जबलपुर। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने एमबीबीएस छात्रों की आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेशनल मेडिकल कमीशन की कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन गाइडलाइन के अनुरूप नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सितंबर 2026 में आयोजित होने वाली एमबीबीएस परीक्षाओं से यह नया पैटर्न प्रभावी होगा। इस बदलाव का सीधा असर 2019 और उसके बाद प्रवेश लेने वाले सभी सीबीएमई बैच के विद्यार्थियों पर पड़ेगा। कुलपति डॉ. अशोक खंडेलवाल के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. आदित्य ठाकुर ने बताया कि अब छात्रों को रटने के बजाय विषयों को समझकर उत्तर देने होंगे, जिससे उनके तार्किक कौशल का बेहतर आकलन हो सकेगा।

परीक्षा के नए स्वरूप में कुल 100 अंकों का होगा प्रश्नपत्र

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा

जारी सूचना के अनुसार एमबीबीएस की सैद्धांतिक परीक्षा अब कुल 100 अंकों की होगी। इसे पांच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि छात्रों की गहन समझ की परीक्षा ली जा सके। नए पैटर्न में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो प्रति प्रश्न 1 अंक यानी कुल 10 अंक के रहेंगे। इसके अलावा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 10 अंक का रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 तय की गई है जिनमें 1 प्रश्न एटॉम आधारित होगा और प्रत्येक 7 अंक के रहेंगे, जिसका कुल योग 35 अंक होगा। अप्लाइड प्रश्न 5 होंगे जो क्लीनिकल परिदृश्य पर आधारित रहेंगे और प्रति प्रश्न 5 अंक यानी कुल 25 अंक के होंगे। अंत में 5 तार्किक यानी रीजनिंग प्रश्न होंगे जो प्रति प्रश्न 4 अंक यानी कुल 20 अंक के होंगे।

नई व्यवस्था पूरी तरह लागू

पहले एमबीबीएस की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र का स्वरूप काफी अलग था। उस दौरान 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते थे जिनमें प्रति प्रश्न 20 अंक निर्धारित थे। साथ ही 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे जिनमें प्रति प्रश्न 5 अंक मिलते थे। इसके अलावा 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे जिनमें प्रति प्रश्न 2 अंक मिलते थे और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के होते थे। इस पुरानी पद्धति को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अपलोड कर दी है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दुविधा न हो। सभी संबंधित मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों को इस नए पैटर्न की जानकारी दें ताकि वे परीक्षा की तैयारी उसी के अनुसार सुनिश्चित कर सकें।

एक नजर में

सिंचाई मोटर एवं 100 पाईप चोरी

जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत पिपरिया स्थित खेत से सिंचाई मोटर, 100 पाईप चोरी हो गए। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा निवासी बजरंग नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी खेती ग्राम चनेरी पिपरिया बरगी में है । माह जून में खेती का काम खत्म होने के बाद खेत में उपयोग की गयी पाईप एवं खेत में बने मकान के पास मोटर खुले में छोडकर अपने घर चला गया था। बुधवार सुबह 10 बजे खेत जाकर देखा तो मकान के बाजू में रखे सिंचाई के 100 पाईप एवं 2 एचपी की एक मोटर गायब थे।

एक ट्रेन से कटा, दूसरे ने लगाई फांसी

जबलपुर । कोतवाली थाना अंतर्गत पंजाब बैंक कॉलोनी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कछपुरा-भेड़ाघाट सेक्शन के बीच युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है ।

कोतवाली पुलिस ने बताया कि मोहन चौधरी 65 वर्ष निवासी पंजाब बैंक कॉलोनी शिवधाम ने सूचना दी कि बेटे अंकितचौधरी 24 वर्ष ने कमरे में पंखे के कुंदे में नाईलोन की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । इसी प्रकार संजीवनी नगर पुलिस ने बताया कि अप ट्रेक पर कछपुरा-भेड़ाघाट सेक्शन के बीच अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास जारी है ।

इस सत्र के अकादमिक कैलेण्डर में छात्रसंघ चुनाव का होगा प्रावधान

जबलपुर। मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ को शासन की ओर से बताया गया कि वर्ष 2026-27 के अकादमिक कैलेण्डर तैयार किया जा रहा है, जिसमें छात्रसंघ चुनाव का प्रावधान होगा। उक्त जवाब पर न्यायालय ने दो सप्ताह में अकादमिक कैलेण्डर पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को निर्धारित की है। दरअसल यह जनहित याचिका अदनान अंसारी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2017 से प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया ठप है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप ने तर्क दिया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदित लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभावी पालन नहीं कर रही है, जिससे विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर अंतिम चरण में है और इस बार उसमें छात्रसंघ गठन संबंधी प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में कैलेंडर पेश करने के निर्देश दिये है।

लावारिस बुजुर्ग की मौत, मोक्ष बनी मददगार

जबलपुर। मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर एक लावारिस बुजुर्ग की मौत के बाद सामाजिक संस्था मोक्ष टीम ने उनका अंतिम संस्कार कराया। जानकारी के अनुसार, स्टेशन परिसर के बाहर करीब 65-70 वर्ष के एक अज्ञात बुजुर्ग मृत अवस्था में पाए गए थे। रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त न होने पर तत्काल इसकी सूचना मोक्ष मानव सेवा एवं जन उत्थान समिति को दी। सूचना मिलते ही मोक्ष संस्था के संयोजक आशीष ठाकुर के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिसिया कार्रवाई और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ तिलवारा श्मशान घाट ले जाया गया। वहां संस्था के सदस्यों ने पूर्ण हिंदू रीति-रिवाज और सम्मान के साथ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इस विदाई बेला में मोक्ष टीम के सदस्य वीरू, योगेश कोरी, अमर गुप्ता, सतीश जायसवाल, सचिन स्वामी एवं रतन झा उपस्थित रहे।

लिंक पर क्लिक करते ही दंपत्ति के खातों से उड़े 4 .94 लाख

ऑनलाइन डॉक्टर सर्च करना पड़ा भारी

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत हाथीताल कॉलोनी में गूगल पर स्किन डॉक्टर का नंबर सर्च करना महंगा साबित हुआ। दरअसल जालसाजों ने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के नाम पर महज 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा और झांसे में लेकर दंपत्ति के दो अलग-अलग बैंक खातों से कुल 4,94,601 पार कर दिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि मूलत: ग्राम खटखरी थाना शाहपुर, जिला मऊगंज के रहने वाले 51 वर्षीय राकेश कुमार गुप्ता वर्तमान में गोरखपुर के हाथीताल कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी सविता गुप्ता को स्किन की समस्या थी। इसी सिलसिले में राकेश अपने मोबाइल पर गूगल के जरिए किसी अच्छे स्किन डॉक्टर का नंबर तलाश रहे थे। गूगल से मिले एक नंबर पर जब उन्होंने संपर्क किया, तो थोड़ी देर बाद उन्हें एक अन्य नंबर से कॉल आया।

फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर से दिखाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसने राकेश के मोबाइल पर एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक के जरिए 10 रुपये का भुगतान करते ही रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाएगा। राकेश ने उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी कारणों से वह भुगतान असफल हो गया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक बीमा पॉलिसी ली, जिसके लिए उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 16,500 का भुगतान किया। संभवत: इसी दौरान या पहले से हैक हो चुके डिवाइस के कारण जालसाज उनके खातों तक पहुंच गए। जालसाजों ने राकेश और उनकी पत्नी के खातों को निशाना बनाते हुए कुल 11 बार में कुल 4,94,601 पर रूपये निकाल लिए।

ओबीसी आरक्षण मामला : कुल आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर केंद्रित रही बहस

आज भी विशेष बेंच के समक्ष ढाई बजे से जारी रहेगी सुनवाई

जबलपुर। हाइकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष पीठ ने बुधवार को मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में मेरिट पर नियमित सुनवाई शुरू की। पहले दिन आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने से आरक्षण की 50 प्रतिशत संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता है। विस्तृत बहस पूरी नहीं हो सकी। विशेष पीठ ने मामले की अगली सुनवाई आज गुरुवार दोपहर ढाई बजे निर्धारित की है।

विशेष पीठ के समक्ष वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली 91 याचिकाओं पर प्रतिदिन सुनवाई हो रही है।

बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। उनकी दलीलें गुरुवार को भी जारी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि यह विवाद पिछले सात वर्षों से न्यायिक विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से वापस आने के बाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है।

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के कारण प्रदेश की अनेक सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का लाभ फिलहाल लागू नहीं हो सका है। इसलिए इस मामले के अंतिम निर्णय पर लाखों अभ्यर्थियों और राज्य सरकार, दोनों की निगाहें टिकी हैं।

चेक बाउंस, आरोपी को 3 माह की सश्रम कैद

जबलपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को परिवादी को कुल 1,44,200 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। यह राशि 80 हजार रुपये के चेक के बदले 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिकर एवं वाद व्यय को मिलाकर निर्धारित की गई है। प्रकरण के अनुसार, आरोपी अर्पण सिंह ने वर्ष 2017 में अपने विवाह के खर्च के लिए नीरज मिश्रा से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मांगी थी। इस पर नीरज मिश्रा ने सद्भावना के तहत 80 हजार रुपये उधार दिए। बाद में रकम वापस मांगने पर आरोपी ने अपने बैंक खाते का 80 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक हस्ताक्षर में भिन्नता एवं खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा, जो आरोपी को प्राप्त हुआ, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।

भुगतना होगा कारावास

मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना सोनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अर्पण सिंह को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही परिवादी को 1,42,200 रुपये प्रतिकर तथा 2,000 रुपये वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता ए .के . भगत एवं शिवम गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की।

बिजली कर्मी पर हमला कर की लूट

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत बब्बा ढाबा के पास देर रात स्कूटी सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने एक बिजली कर्मचारी पर हमला कर मोबाइल, नकदी सहित चांदी की अंगूठी छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, ग्राम डूंडी निवासी चंद्रभान झारिया (32) मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शारदा नगर रिछाई में प्राइवेट काम करते हैं। बीती रात करीब 12:15 बजे वे अपनी ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बब्बा ढाबा के आगे रेत स्टॉक के पास पहुंचे, पीछे से एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार तीन युवक आए। बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल के आगे स्कूटी अड़ाकर उन्हें रोका और विवाद करते हुए बोले, कैसी गाड़ी चला रहा है, शराब पिया है क्या? पीड़ित कुछ समझ पाता, इससे पहले ही तीनों बदमाशों ने चंद्रभान को घेर लिया। झपटमारी और विरोध के दौरान बदमाशों ने चंद्रभान के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे उनकी दाहिनी आंख के पास गंभीर चोट आई। इसके बाद बदमाशों ने उनके हाथ से ओप्पो कंपनी का मोबाइल, जेब में रखा पर्स जिसमें 4-5 हजार रुपये नगद थे और दाहिने हाथ की चांदी की अंगूठी जबरन निकाल ली।

28 घंटे बाद खत्म हुआ शिक्षा सुधार को लेकर अनशन

प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन

नवभारत, जबलपुर। शाहपुरा क्षेत्र के निजी विद्यालयों में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर जारी 28 घंटे का आमरण अनशन बुधवार को प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। अपर कलेक्टर मरावी ने धरना स्थल पहुंचकर अनशनकारियों से चर्चा की और शिकायतों की निष्पक्ष जांच तथा नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा की अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

42,803 मतपत्रों की गिनती पूरी

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव-2026 की मतगणना प्रथम वरीयता के अंतिम चरण में पहुंच गई है। बुधवार को ओबेदुल्लागंज, गैरतगंज, बैतूल, बेगमगंज, उदयपुरा, गोहद, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, जीरापुर, खिलचीपुर, सैलाना, जावरा, आलोट और रतलाम के मतपत्रों की गिनती शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से पूरी हुई। अब तक 42, 803 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। मुख्य चुनाव अधिकारी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के अनुसार पूरी प्रक्रिया प्रत्याशियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराई जा रही है। वर्तमान चरण में प्रथम वरीयता के मतों में राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, आरके सिंह सैनी, एचपी जय हार्डिया और अखिलेश कुमार सक्सेना को बढ़त मिली है। महिला प्रत्याशियों में प्रतीका पाठक, अनुल पटेल, प्रतिभा बलिया, रेशम ऋतु जैन और अंजना कुशवाहा आगे चल रही हैं। अधिकारियों ने चुनाव में महिला अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अब तक करीब 62 हजार मतों में से 42,803 मतपत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है।

सौगात | साल के अंत तक संस्कारधानी को मिलेगी सौ इलेक्ट्रिक बसें

जुलाई और अगस्त में आएगी 20-20 बसों की खेप

नवभारत, जबलपुर। शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द शुरू होने जा रहा है। योजना के तहत जबलपुर को कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। पहले चरण में जुलाई में 20 और अगस्त में 20 बसें मिलेंगी। इस तरह अगस्त तक शहर के पास 40 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी, जबकि शेष बसें दिसंबर तक मिलने की संभावना है।

यहाँ की गई है चार्जिंग व्यवस्था

इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए कठौंदा डिपो में विशेष

व्यवस्था की जा रही है। बसें रातभर चार्ज होंगी और दिनभर विभिन्न रूटों पर यात्रियों को सेवा देंगी। इससे ईंधन खर्च कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा प्रारंभिक चरण में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जबलपुर रेलवे स्टेशन से पनागर, भेड़ाघाट से पनागर तथा रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट रूट पर प्रस्तावित है। इन मार्गों पर यात्रियों को स्वच्छ, आरामदायक और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।

दिसंबर तक पूरा होगा बेड़ा

अधिकारियों के अनुसार सभी 100 इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर तक शहर को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से विभिन्न रूटों पर संचालन बढ़ाया जाएगा, जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

फैक्ट फाइल

कुल बसें	100 इलेक्ट्रिक बसें
जुलाई 2026	20 बसें मिलने की संभावना
अगस्त 2026	20 और बसें मिलेंगी (कुल 40 बसें)
शेष बसें दिसंबर 2026	तक सभी 100 बसें उपलब्ध होने का लक्ष्य
चार्जिंग व्यवस्था	कठौंदा स्थित डिपो में रातभर होगी चार्जिंग
संचालन	चार्जिंग के बाद बसें पूरे दिन शहर में संचालित होंगी
प्रमुख प्रस्तावित रूट	रेलवे स्टेशन - पनागर, भेड़ाघाट - पनागर एवं शहर के अन्य रूट पर दौड़ेगी बसें

रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर हुआ मंथन

टीटीई रेस्ट हाउस में एसी और संरक्षा स्टाफ को साप्ताहिक रेस्ट पर सहमति

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ (डब्ल्यूसीआरएमएस) की दो दिवसीय महाप्रबंधक पीएनएम बैठक के पहले दिन अध्यक्ष सी.एम. उपाध्याय और महामंत्री अशोक शर्मा ने महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह के समक्ष रेल कर्मचारियों से जुड़ी दर्जनों लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक में मेडिकल डी-कैटेगराइज्ड मामलों के शीघ्र निराकरण, दयाधार नियुक्ति, महिला ट्रैक मेंटेनरों के कैडर परिवर्तन, लंबित पदस्थापन, म्यूचुअल ट्रांसफर, ट्रैक मशीन में रिक्त पदों की भर्ती, क्वार्टरों के रखरखाव, बेहतर सेफ्टी शूज, ओटी भत्ता, जीडीसीई एलडीसी

परीक्षा समय पर कराने सहित विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

सुविधाओं में हो सुधार

बैठक में इटारसी में नए टीटीई रेस्ट हाउस के निर्माण, मौजूदा टीटीई रेस्ट हाउस एवं डिस्पेंसरी में एयर कंडीशनर लगाने, श्वेतांबरी रेस्ट हाउस की सुविधाओं में सुधार, संरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम, एसएंडटी स्टाफ की कार्य परिस्थितियों में सुधार, रनिंग स्टाफ की समस्याओं के समाधान, धूल एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर भी सकारात्मक सहमति बनी। बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संघ के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।